माही प्रोजेक्ट • माही बांध एवं नर्मदा नहर की संयुक्त परियोजना का सर्वे कराने की मांग

डीपीआर बनाने को लेकर एजेंसी निर्धारण के लिए लिखा पत्र

भास्कर न्यूज़ | जालोर

राज्य बजट 2023-24 में घोषित माही नदी को लूनी से जोड़ने के साथ पश्चिमी राजस्थान को लाभान्वित करने के लिए प्रोजेक्ट की क्रियान्विति को जल संसाधन विभाग जोधपुर के चीफ इंजीनियर ने जयपुर चीफ इंजीनियर को पत्र लिखा है। 9 मार्च को जल संसाधन विभाग जोन जोधपुर के मुख्य अभियंता अमरसिंह ने पत्र में लिखा है कि प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए माही नदी को लूनी नदी से जोड़ने के साथ माही बांध एवं नर्मदा नहर की संयुक्त परियोजना का सर्वे करवाकर पश्चिमी राजस्थान केनाल परियोजना की डीपीआर बनाए जाएगी। इस कड़ी में आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए एजेंसी का जल्द से जल्द निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही 3 माह के भीतर ही निरीक्षण की रिपोर्ट, प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ड्राफ्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा सके। उसके बाद 90 दिन की अवधि में फाइनल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जा सके।

इसलिए खास है मामला

माही परियोजना की क्रियान्विति के लिए राजस्थान किसान संघर्ष समिति की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिसमें गुजरात और राजस्थान सरकार के बीच 1966 को हुए समझौते के अनुसार माही परियोजना से जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिले को पानी उपलब्ध करवाने की मांग की गई थी। याचिका पर उच्च न्यायालय की ओर से जारी निर्देश पर राज्य बजट 2023-24 में इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा की गई। प्रोजेक्ट की भविष्य में क्रियान्विति होने पर तीनों जिले के सूखे क्षेत्र को सिंचित किया जाना हैं।

nwda.gov.in